वार्षिक योजना 2011–12 की प्राथमिकताओं की मध्यावधि समीक्षा एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के सुदृढ़ीकरण एवं युक्तिकरण हेतु दिनांक 20–21 सितम्बर, 2011 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों की कार्यवाही।

सर्वप्रथम मुख्य सचिव महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्य संसदीय सचिवगण, माननीय विधायकगण, प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा सभी उपस्थित अधिकारियों का बैठक में भाग लेने हेतु स्वागत किया। उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि गत 27 एवं 28 जनवरी, 2011 को आयोजित वार्षिक बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना में इस मध्यावधि समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है।

माननीय मुख्य सचिव ने बताया कि इस बैठक में माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं की मध्यावधि समीक्षा के अतिरिक्त 12वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की जाएगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के निर्धारण हेतु योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा दृष्टिकोण पत्र पर विचार–विमर्श शुरू कर दिया गया है तथा शीघ्र ही राज्य–वार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। यह बैठक 12वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु माननीय विधायकों एवं माननीय सांसदों के विचार जानने हेतु बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। दिनांक 27 व 28 जनवरी, 2011 को हुई बैठक में माननीय विधायकों द्वारा उठाए गए अधिकतर मुद्दों पर कार्यवाही की जा चुकी है। उन्होंने प्रशासनिक सचिवों एवं विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया कि इस बैठक में उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों पर कार्यवाही सुनिश्चित करके माननीय विधायकों को सूचित करें।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि सरकार सभी क्षेत्रों के त्वरित व संतुलित विकास एवं समाज के सभी वर्गों को सामाजिक – आर्थिक न्याय देने के लिए वचनबद्ध है। इन बैठकों के माध्यम से बहुत ही बहुमूल्य एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं तथा उसी के परिणामस्वरूप प्रदेश को विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय एजैंसियों द्वारा उत्कृष्ट आंका गया है। 20–सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रदेश ने पूरे देश में लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जोकि सभी के लिए बहुत गर्व की बात है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि योजना विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वह सभी माननीय विधायकों को उनके चुनाव क्षेत्र से सम्बन्धित अव्यवहार्य स्कीमों की सूचना उपलब्ध करवाएं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह सूचना माननीय विधायकों को प्राप्त हो गई होगी। उन्होंने माननीय विधायकों से अनुरोध किया कि वे इन अव्यवहार्य स्कीमों के स्थान पर नई स्कीमें प्रस्तावित करें ताकि शीघ्रातिशीघ्र इन स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा सके।

उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष 11वीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2012-13 से 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा। इन बैठकों में माननीय विधायकों की प्राथमिकता स्कीमों की समीक्षा के अतिरिक्त प्रदेश के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित की जाने वाली प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की जाएगी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में देश की विकास दर 8.2 प्रतिशत आंकी गई है। भारत सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य 9.0 प्रतिशत रखा गया है। प्रदेश की विकास दर भी देश की विकास दर के बराबर है परन्तु 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के लिए 9.5 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा है। उन्होंने सभी माननीय प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव दें। प्रदेश में जी.एस.डी.पी. को बढ़ाने तथा विकास की गति में और तीव्रता लाने हेतु सार्वजनिक - निजी भागीदारी पर भी सुझाव देने का आग्रह किया गया।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रों में खोले गए संस्थानों के सुदृढ़ीकरण एवं युक्तिकरण हेतु सुझाव मांगे। उन्होंने प्रदेश में मितव्ययता उपायों, अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु सम्भावनाओं तथा प्रदेश में बेहतर प्रशासन पर भी सुझाव आमंत्रित किए। माननीय विधायकों से आग्रह किया गया कि वे अपने सुझाव लिखित रूप में 5 अक्तूबर तक निर्धारित प्रपत्र पर भरकर योजना विभाग को भेजें ताकि प्रदेश स्तर पर एक समेकित नीति निर्णय लिया जा सके।

माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने बताया कि वर्तमान वित्तीय परिवेश में प्रदेश की प्राथमिकताओं को 12वीं पंचवर्षीय योजना में समायोजित करना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को तलाशने एवं उपलब्ध संसाधनों को विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार की नीति अनुसार सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य,

स्वरोजगार, सम्पन्नता एवं स्वावलम्बन को प्राथमिकता दी गई है तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी इन प्राथमिकताओं को केन्द्र बिन्दु माना जाएगा। हम इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि उन्होंने योजना आयोग, भारत सरकार से 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए ₹27,556 करोड़ के परिव्यय की मांग की है। प्रस्तावित परिव्यय 11वीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय से दो गुना अधिक है।

प्रधान सचिव (योजना) ने बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के निर्धारण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दृष्टिकोण पत्र जारी किया है। उन्होंने इस दृष्टिकोण पत्र में निर्धारित मदों का विस्तृत विवरण बैठक में दिया।

दो दिवसीय बैठकों में उठाई गई मदों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है :–

जिला शिमला

1. श्री नंद लाल (रामपुर)

(1) फॉरेस्ट क्लीयरेंस के कारण निम्न पांच सड़कों का कार्य अवरुद्ध है। उन्होंने इन सड़कों की फॉरेस्ट क्लीयरेंस करवाने का आग्रह किया:–

- कोरीधार–कांगला–चूंजा सड़क।
- नोगली पावर हाऊस – देवतन– कलाणा सड़क।
- लालसा–चांजल–चिकसा मझाली सड़क
- लाहरू–खलेड़ा सड़क
- उरटूधार सड़क।

निम्न सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए:–

- काशा पाठ –डडोल
- कूट – क्याव

– लोक निर्माण विभाग

(2) पाठशाला भवन, जिनमें छोटे–छोटे कार्य शेष बचे हैं, उन्हें शीघ्र पूर्ण किया जाए।

– लोक निर्माण, प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा विभाग

(3) राष्ट्रीय उच्च मार्ग–22 के अन्तर्गत अक्षदेवी, काथ नगर, कनेरी, बरोनी नाला पर भू–स्खलन के कारण अवरुद्ध सड़कों की समस्या का ठोस समाधान निकाला जाए।

– लोक निर्माण विभाग

(4) दरशाल नामक स्थान पर निर्मित पुल भारी बरसात के कारण बह गया है, जिसका पुर्ननिर्माण किया जाए।

– लोक निर्माण विभाग

(5) प्रदेश में कुशल कामगारों की कमी है जिसे बढ़ाने हेतु प्रयास किये जायें तथा प्रदेश के उद्योगों में हिमाचलियों को 70 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित किया जाए।

– तकनीकी शिक्षा/ श्रम एवं रोजगार विभाग

(6) रामपुर निर्वाचन क्षेत्र में डॉक्टरों की भारी कमी है जिसे दूर किया जाए।

– स्वास्थ्य विभाग

(7) रामपुर अस्पताल में खराब पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन को ठीक किया जाए।

– स्वास्थ्य विभाग

2. श्री खुशी राम बालनाहटा (रोहड़ू)

(1) स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए।

– स्वास्थ्य विभाग

(2) डोडरा क्वार में सड़क के निर्माण में कमियों को ठीक कर इसे यातायात योग्य किया जाए।

–परिवहन/लोक निर्माण विभाग

(3) लाल ढंग – पांवटा होकर सरस्वती नगर तथा शिमला – नारकंडा– वांगतु राष्ट्रीय उच्च मार्गों को जोड़ने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(4) खदराला स्थित वन विभाग के ऐतिहासिक विश्राम गृह की शीघ्र मुरम्मत की जाए ताकि उक्त विश्राम गृह को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने में मदद मिले।

–वन विभाग

3. श्री सुभाष मंगलेट (चौपाल)

(1) उत्तराखंड की तरफ से छैला को राष्ट्रीय उच्च मार्ग से जोड़ने हेतु प्रयास किये जाएं तथा बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मुरम्मत हेतु तुरन्त कार्रवाई की जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(2) नई निर्मित सड़कों, जो कि विभाग द्वारा पास की जा चुकी हैं, पर नए बस रूट दिये जाएं तथा इन पर बसें चलाई जाएं।

–लोक निर्माण विभाग/ परिवहन विभाग

(3) राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ईला, जिसे कि एक निजी भवन में चलाया जा रहा है, में कमरों का प्रावधान किया जाए।

–शिक्षा विभाग

(4) नेरवा, कुपवी तथा चौपाल में डाक्टरों की कमी को शीघ्र दूर किया जाए तथा इन अस्पतालों में नियमित डाक्टर तैनात किए जाएं। नये खुले चिकित्सा संस्थानों में भवन निर्माण तथा डाक्टरों एवं स्टाफ को आवासीय सुविधा प्रदान की जाए।

–स्वास्थ्य विभाग

4. श्री सुरेश भारद्वाज (शिमला शहरी)

(1) शिमला शहर में भीड़–भाड़ एक मुख्य समस्या है। इस समस्या से निजात हेतु निम्न पग उठाए जाएंः–

- शहर में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाए जहां पार्किंग का निर्माण किया जा सके। अब तक चिन्हित स्थानों पर शीघ्र पार्किंग निर्माण की व्यवस्था की जाए। इसके अतिरिक्त नगर निगम, जहां संभव हो, छोटी–2 पार्किंग स्थलों का निर्माण करे।
- बाई पास स्थित कूड़ा संयंत्र, जो कि कुछ ही दिनों बाद तारा देवी स्थानांतरित होने वाला है के स्थान पर अनाज मण्डी व सब्जी मण्डी को स्थानांतरित किया जाए। इससे न केवल शहर में भीड़ की कमी होगी अपितु किसान/ बागवान भी अनावश्यक भाड़े से बच सकेंगे।
- रेलवे स्टेशन से माल गोदाम तक बिछी रेलवे लाईन को सामान ढोने के लिये प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो इस स्थान पर पार्किंग के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय से मामला उठाया जाए।
- शिमला शहर में मोनो रेल की व्यवस्था किये जाने पर विचार किया जाए।
- शहर में दो या तीन स्थानों पर फलाई ओवर निर्मित किए जाएं।

- शहर में प्रस्तावित तीन सुरंगों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए।

–नगर निगम, शिमला/परिवहन विभाग

(2) कमला नेहरू अस्पताल को आई.जी.एम.एस. स्थानांतरित करने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(3) स्वास्थ्य शिक्षा में फैक्ल्टी डाक्टर की भारी कमी को देखते हुए मैडिकल कॉलेज के वरिष्ठ फैक्ल्टी डाक्टरों की सेवानिवृति आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाए ताकि प्रदेश में डाक्टरों की कमी की समस्या का हल हो सके।

–स्वास्थ्य विभाग

(4) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत जो डी.पी.आर. अब तक नहीं भेजी जा सकी है उसे शीघ्र भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए तथा केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी आवास योजना का लाभ उठाने के उद्देश्य से अधिक से अधिक डीपीआर बनाकर केंद्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी जाए।

–नगर निगम, शिमला

(5) सरकारी नीति अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दो अनुसूचित जाति के गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। चूँकि शिमला (शहरी) चुनाव क्षेत्र में कोई गांव नहीं पड़ता, इसलिए इस क्षेत्र की दो हरिजन बस्तियों को मॉडल हरिजन बस्ति के रूप में अपनाया जाए व उन्हें विकसित किया जाए।

–पर्यटन विभाग/नगर निगम, शिमला

(6) हिमफैड पैट्रोल पंप से सुरंग निर्माण हेतु विचार किया जाए ताकि सचिवालय के आस –पास भीड़ भाड़ को कम किया जा सके।

–नगर निगम, शिमला

(7) पर्यटन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ताकि प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा मिले।

–पर्यटन विभाग

(8) प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत कृषि क्षेत्र को और बढ़ावा दिया जाए ताकि प्रदेश की आय में वृद्धि हो।

–कृषि विभाग

5. श्री सोहन लाल (कसुम्पटी)

(1) कसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र की निम्न सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बनवाया जाएः–

(क) घरोग नाथ सड़क

(ख) डाक बंगला–घरेच सड़क

(ग) समरहिल–सांगटी सड़क

(घ) भूरोरा–काली हट्टी सड़क

(ङ) धामी–बैंज सड़क :

(च) पड़ेच–डफोग–मघेच वाया बथयार कड़ेच

–लोक निर्माण विभाग

(2) विधायक प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत संस्तुत ऐसी सिंचाई स्कीम जिन्हें विभाग द्वारा अव्यवहार्य घोषित किया गया है, को क्षेत्र में जल की उपलब्धता के दृष्टिगत पुर्नविचार किया जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(3) कसुम्पटी चुनाव क्षेत्र, विशेषकर कुफरी, में पर्यटन स्थलों का चयन कर उन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।

–पर्यटन विभाग

(4) शिमला के आस–पास के क्षेत्र की 60 कि0मी0 तक दूरी की लोकल बसों को पुराने बस अड्डे में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाए ताकि निर्वाचन क्षेत्र के किसानों/बागवानों को अपना उत्पादन सब्जी मण्डी में पहुंचाने में ज्यादा परेशानी न हो।

–परिवहन विभाग

(5) नया बस अड्डा क्योंकि शिमला शहर से दूर है तथा रात को आने वाले पर्यटकों/लोगों को शहर तक टैक्सी के माध्यम से आना पड़ता है। अतः नये बस अड्डे से शहर के विभिन्न स्थानों की टैक्सी दरें निर्धारित की जाएं।

–परिवहन विभाग

(6) शिमला स्थित सब्जी मण्डी शहर के बीचो–बीच स्थित होने के कारण किसानों, बागवानों को अपना उत्पाद यहां पहुंचाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस सब्जी मण्डी को टूटू–तारा देवी सड़क पर जहां

खाली भूमि उपलब्ध है, अथवा बाई पास पर कहीं भी खाली जगह पर स्थानांतरित किया जाए।

–नगर निगम, शिमला

(7) टूटू क्षेत्र में नए सम्मिलित क्षेत्रों में सीवरेज की व्यवस्था की जाए।

–नगर निगम

6. श्रीमती विद्या स्टोक्स (कुमारसैन)

(1) निर्माणाधीन बैहना खड्ड पेयजल योजना, जिसके अन्तर्गत पांच पंचायतें आती हैं, को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि स्थानीय लोगों की पीने के पानी की समस्या का समाधान हो।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(2) पर्यटन के दृष्टिगत शिमला शहर में मोनो रेल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

–नगर निगम, शिमला

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक बैंक स्थापित किये जायें।

–निदेशक, संस्थागत निवेष

(4) खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में अधिक से अधिक स्टेडियमों का निर्माण किया जाए।

–युवा एवं खेल विभाग

सोलन जिला

1. श्री गोबिंद राम शर्मा (अर्की)

(1) दाड़लाघाट तथा मांगल (सीमेंट फैक्टरी के कारण) तथा दाड़ला– डोमैहर– दिग्गल– नालागढ़ सड़कों पर भी यातायात की समस्या के निदान हेतु दाड़ला फारेस्ट हाऊस से खरडहट्‌टी तक डबल रोड बनाया जाए। दाड़ला मोड़ से मलोखर तक सड़क निर्मित की जाए तथा मलोखर में सुरंग का निर्माण किया जाए।

– लोक निर्माण विभाग

(2) उप–तहसील दाड़लाघाट हेतु विभिन्न नए पदों का सृजन किया जाए।

– राजस्व विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग

(3) दाड़लाघाट में सीवरेज की व्यवस्था की जाए।

– सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(4) दिग्गल में कॉलेज खोला जाए।

– उच्च शिक्षा विभाग

(5) जयनगर तथा बाघ का जुब्बड़ में निर्माणाधीन विश्राम गृहों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए।

– वन विभाग

(6) घनागूघाट तथा चमदार में +2 स्कूल खोले जाएं।

– उच्च शिक्षा विभाग

(7) पं0 दीन दयाल उपाध्याय किसान बागवान समृद्धि योजना के अन्तर्गत पॉली हाऊसिज़ बनाने के लिए किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है तथा शेष 50 प्रतिशत राशि पर किसानों को बैंकों को 14 प्रतिशत ब्याज अदा करना पड़ रहा है। प्रदेश में किसानों की स्थिति के दृष्टिगत सब्सिडी राशि को बढ़ाने पर विचार किया जाए।

– कृषि विभाग

2. डॉ0राजीव सहजल (कसौली)

(1) विधायक प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत नाबार्ड से स्वीकृत निम्न स्कीमों, जिन्हें विभाग द्वारा अस्वीकृत किया गया है, को पुनः बहाल किया जाएः–

- **भोजनगर–नेरी कलां वाया टिक्करी सड़क**
- **माटा घाट – गईघाट वाया बरगयाना**

(2) निम्न सड़कों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएः–

- **बणाघाट–तरासड़ी सड़क**
- **परवाणु –गडयार रोड (मैटलिंग एवं टारिंग) का शेष कार्य।**

–लोक निर्माण विभाग

(3) कसौली निर्वाचन क्षेत्र में कॉलेज खोला जाए।

–उच्च शिक्षा विभाग

जिला सिरमौर

1. श्री गंगू राम मुसाफिर(पच्छाद)

(1) 12वीं पंचवर्षीय योजना बनाते समय पूर्व योजनाओं की कमियों एवं उपलब्धियों पर गंभीर चिंतन किया जाए तथा रह गई कमियों को दूर किया जाए।

–योजना विभाग

(2) पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किये जाएं।

–पर्यटन विभाग

(3) शिक्षा संस्थानों में रिक्त पदों को भरा जाए।

–प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा विभाग

(4) पच्छाद क्षेत्र के सराहां में नया कॉलेज खोला जाए।

–उच्च शिक्षा विभाग

(5) बरसात से क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थिति सुधारने हेतु और अधिक धन का प्रावधान किया जाए।

–लोक निर्माण विभाग

2. डॉ0 प्रेम सिंह (रेणूका)

(1) कम विद्यार्थी होने के कारण बंद की गई प्राथमिक पाठशालाओं को उसी विधानसभा क्षेत्र में, जहां आवश्यकता हो, में खोला जाए।

–प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

(2) कोठी धीमान में पाठशाला के साथ खुले शराब के ठेके को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए।

– आबकारी एवं कराधान विभाग

(3) संगड़ाह, ददाहू, नौहराधार तथा हरिपुरधार में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान हेतु बस अड्डों का निर्माण किया जाए।

–परिवहन विभाग

(4) उद्यान एवं कृषि विभागों में अधिकारियों व कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए।

–कृषि/उद्यान विभाग

(5) नौहराधार, संगड़ाह तथा हरिपुरधार में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य उप मण्डलों के लिये भवनों का निर्माण किया जाए तथा नौहराधार स्थित मण्डल के कार्यालय भवन को शीघ्र पूर्ण किया जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(6) मिल्क चिलिंग प्लांट, रेणूका हेतु भूमि उपलब्ध करवाई जाए।

–दुग्ध प्रसंग/ राजस्व विभाग

(7) सड़कों के रख–रखाव हेतु धनराशि की व्यवस्था की जाए।

–लोक निर्माण विभाग

3. श्री हर्षवर्धन चौहान (शिलाई)

(1) पांवटा–शिलाई राष्ट्रीय उच्च मार्ग के रख–रखाव हेतु धनराशि की व्यवस्था की जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(2) शिवा–बनौर सड़क के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(3) सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाऊ सिंचाई योजनाओं के लिए थ्री फेज लाईनों की व्यवस्था की जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(4) प्राथमिक पाठ्शालाओं में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा शिक्षा की गुणवत्ता की ओर ध्यान दिया जाए ताकि छात्रों की संख्या में कमी को रोका जा सके।

–प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

(5) कठिन तथा दुर्गम क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए अलग कॉडर बनायाजाए तथा प्रत्येक नवनियुक्ति पर पांच वर्ष कठिन क्षेत्रों में सेवाएं देने की शर्त रखी जाए।

–समस्त विभाग

(6) बकरास, टटियाना, मिल्ला, खुब–द्राबल इत्यादि +2 पाठशालाओं में खाली पड़े प्रवक्ताओं के पदों को शीघ्र भरा जाए।

–उच्च शिक्षा विभाग

(7) कांटी मशवा, कमरऊ, आदि स्वास्थ्य केन्द्रों में खाली पड़े डाक्टरों के पदों को शीघ्र भरा जाए।

–स्वास्थ्य विभाग

(8) वोल्टेज की समस्या को सुधारने हेतु शिलाई में 16 के. वी. के ट्रांसफार्मर के स्थान पर थ्री फेज के 25 के.वी. के ट्रांसफार्मर लगाये जायें।

–हि0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड

(9) शिमला–रोनहाट बस को यथावत् रखा जाए तथा धार चानणा के लिए नई बस चलाई जाए।

–परिवहन विभाग

(10) पाठशालाओं के लिए एक–2 कमरा अलग–2 स्थानों की बजाए पूर्ण सुनियोजित ढंग से बहुमंजिला भवनों का निर्माण किया जाए।

–प्रारम्भिक/उच्च शिक्षा विभाग

3. श्री कुश परमार (नाहन)

(1) नाहन पेयजल योजना जिसकी अनुमानित लागत 52 करोड़ रुपये है, हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(2) नाहन स्थित फाऊंड्री जो अब बंद हो चुकी है की 28 बीघा भूमि को शिक्षा विभाग को स्थानांतरित किया जाए ताकि यहां पर डिग्री कॉलेज हेतु भवन का निर्माण किया जा सके।

–शिक्षा/सिंचाई एवम् जन स्वास्थ्य विभाग

(3) नाहन पर्यटन परिसर में समुचित स्टॉफ की व्यवस्था की जाए।

–पर्यटन विभाग

(4) अंबाला–देहरादून राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर काला अंब से पावंटा साहिब सड़क की शीघ्र मुरम्मत करवाई जाए।

–लोक निर्माण विभाग

जिला मण्डी

1. श्री कौल सिंह ठाकुर (द्रंग)

(1) सड़क निर्माण हेतु भूमि विवाद तथा अन्य समस्याओं के निदान हेतु स्थानीय प्रतिनिधियों से सहयोग लिया जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(2) विधायक प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत संस्तुत स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र बनाई जाए तथा जहां आवश्यक हो वहां पर इन्हें आउटसोर्स किया जाए।

–लोक निर्माण/ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(3) किसानों/बागवानों की फसलों को जंगली जानवरों तथा आवारा पशुओं से हो रहे नुकसान का शीघ्र समाधान किया जाए।

–वन/ कृषि विभाग

(4) सरकारी विभागों में आपसी समन्वय स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि विकास के कार्य प्रभावित न हो।

–समस्त विभाग

2. श्री रूप सिंह (सुंदरनगर)

(1) प्रदेश के विकास के लिये निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित की जाए तथा परियोजनाएं आबंटित करने से पूर्व संस्थान की पृष्ठभूमि की छानबीन करना सुनिश्चित किया जाए।

–समस्त विभाग

(2) शिक्षा की गुणवत्ता की ओर विशेष ध्यान दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

–प्रारम्भिक/उच्च शिक्षा विभाग

(3) करसोग और सुंदरनगर के मध्य निहरी नामक स्थान पर कॉलेज खोला जाए।

–उच्च शिक्षा विभाग

(4) विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करसोग– सुंदरनगर के बीच निहरी नामक स्थान पर कृषि विपणन मण्डी का उपकेंद्र खोला जाए।

–कृषि विभाग

(5) सलापड़ से तत्तापानी तक 12 कि0मी0 सड़क का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(6) बिलासपुर, सोलन तथा मण्डी जिलों के छात्रों की सुविधा हेतु डैहर में आई.टी.आई. की स्थापना की जाए।

–तकनीकी शिक्षा विभाग

(7) सुंदरनगर स्थित एचपीएमसी के प्लांट को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने हेतु विचार किया जाए।

–एच.पी.एम.सी.

3.श्री दिले राम (नाचन)

(1) संपर्क मार्ग, कनैड, जिसकी अनुमानित लागत 53 लाख रुपये है, हेतु समुचति धनराशि की व्यवस्था की जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(2) मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्यों के लिये सीमेंट के वितरण में कमी की समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए।

–खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

(3) भारी वर्षा से प्रभावित नाचन निर्वाचन क्षेत्र में गरीब लोगों को मकान बनाने हेतु पर्याप्त मुआवजा/सहायता दी जाए।

–राजस्व विभाग

(4) मनरेगा योजना के अन्तर्गत किसानों के खेतों में बाड़ लगाने का प्रावधान किया जाए ताकि आवारा पशुओं से फसलों के नुकसान से बचाव हो सके।

–ग्रामीण विकास विभाग

(5) मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना, जिसके अन्तर्गत क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण कार्य हुए हैं तथा लोगों की आजीविका में बढ़ौतरी हुई है, के विस्तारीकरण हेतु प्रयास किये जाएं।

–मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना/वन विभाग

(6) कमरूनाग एवं शिकारी देवी धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।

–पर्यटन विभाग

(7) देवीधर नामक स्थान पर सुरंग का निर्माण किया जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(8) बिजली दोहन को प्राथमिकता दी जाए ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिलने के साथ–2 प्रदेश का विकास सुनिश्चित हो सके।

–हि० प्र० वि० निगम

4. कर्नल इंद्र सिंह (गोपालपुर)

(1) सीर खड्ड चैनालाईजेशन योजना का कार्य केवल एक एजेंसी को दिया जाए ताकि इसकी देख–रेख ठीक ढंग से हो सके तथा कार्य शीघ्र संपन्न हो।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(2) सरकाघाट सीवरेज योजना के निर्माण को शीघ्र पूरा किया जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(3) बलद्वाड़ा में डिग्री कॉलेज खोला जाए।

–उच्च शिक्षा विभाग

(4) भावंला स्थित औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें लगभग 50 बीघा भूमि उद्योग विभाग के पास है पर उपयुक्त उद्योग लगाने हेतु प्रयास किए जाएं।

–उद्योग विभाग

(5) भारी वर्षा के कारण अवरुद्ध सड़कों के रख–रखाव हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(6) बलद्वाड़ा अस्पताल में स्त्री रोग एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ शीघ्र तैनात किये जाएं तथा यहां कम से कम 100 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।

–स्वास्थ्य विभाग

(7) बलद्वाड़ा क्षेत्र में बी.एस.एन.एल. की कमजोर सेवा में सुधार हेतु उचित कार्रवाई की जाए।

–सामान्य प्रशासन विभाग

5. श्री हीरा लाल (करसोग)

(1) करसोग–छतरी सड़क के अधूरे पड़े मैटलिंग एवं टॉरिंग कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए। करसोग–कोटलु कटांडा, करसोग– परलोग, महुनाग– सकतयाला महुटा– बकसार तथा साकड़ा– बिंदला सड़कों को शीघ्र पूर्ण किया जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(2) आई.टी.आई. भवन निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र दिया जाए।

–तकनीकी शिक्षा विभाग

(3) करसोग स्थित निर्माणाधीन 100 बिस्तरों के अस्पताल में विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी को शीघ्र पूरा किया जाए।

–स्वास्थ्य विभाग

(4) दूध गंगा योजना के अंतर्गत स्वीकृत करसोग स्थित चिलिंग प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाए।

–दुग्ध प्रसंग

6. श्री अनिल शर्मा (मण्डी सदर)

(1) नाबार्ड के तहत स्वीकृत टी.पी.टी.एस. तथा बाई धनयारी सड़कों की प्रशासनिक स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(2) योजनाएं बनाते समय सम्बन्धित विधायक को विश्वास में लिया जाए ताकि व्यवहारिक एवं सही योजनाएं बनाई जा सके ताकि लोगों को इनका अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

–समस्त विभाग

7. श्री प्रकाश चौधरी (बल्ह)

(1) लघु सिंचाई योजना लेदा तथा रिवालसर की डी.पी.आर. को शीघ्र बनाया जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(2) नेरचौक में उप तहसील खोली जाए।

–राजस्व विभाग

(3) रिवालसर में डिग्री कॉलेज खोला जाए।

–उच्च शिक्षा विभाग

(4) बल्ह निर्वाचन क्षेत्र में आई.टी.आई खोली जाए।

–तकनीकी शिक्षा विभाग

(5) लेदा में पी.एच.सी. खोला जाए।

–स्वास्थ्य विभाग

(6) बल्ह क्षेत्र में हवाई पट्टी का निर्माण किया जाए।

–पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग

(7) बल्ह क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह निर्मित किया जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(8) नेरचौक तथा लेदा में पार्किंग की व्यवस्था की जाए।

–शहरी विकास विभाग/ पंचायती राज विभाग

जिला बिलासपुर

1.श्री रणधीर शर्मा (कोट कहलूर)

(1) पंचायत या दूसरे कार्यकारी अभिकरणों द्वारा निर्मित सड़कों को लोक निर्माण विभाग अपने अधिकार में लें तथा इनका रख–रखाव सुनिश्चित करे ताकि ये सड़कें वाहन चलने योग्य बन सकें।

–लोक निर्माण विभाग

(2) नेशनल अथॉरिटी ऑफ इण्डिया को स्वारघाट में सुरंग एवं समानान्तर सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र करने का आग्रह किया जाए। ब्रह्मपुखर–जामली वाया दियोथ सड़क को भी चौड़ा किया जाए। दाड़लाघाट से चलने वाले ट्रकों के लिए सोलन जिला में रामशहर की ओर अन्य सड़क विकसित की जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(3) विकेन्द्रीकृत नियोजन एवं सूखा राहत शीर्षों के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को विभागों के माध्यम से कार्यन्वित करवाया जाए ताकि निर्माण कार्य शीघ्र पूरे किए जा सकें।

–उपायुक्त, बिलासपुर

(4) शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से किसी एक उचित +2 पाठशाला का मॉडल के रूप में चयन करके वहां समस्त आधुनिक शिक्षा सुविधाएं प्रदान की जाएं।

(5) स्वास्थ्य एवम् शिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण को एफ.सी.ए. से बाहर रखा जाए ताकि इन संस्थानों के निर्माण कार्य निर्विघ्न हो सके।

–स्वास्थ्य, प्रारम्भिक/उच्च शिक्षा, वन विभाग

(6) दूर दराज के प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थानों में डाक्टरों के लिये आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाएं। सी.एच.सी. नयना देवी व मार्कंण्डे में अटल स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत एंबुलैंस सुविधा भी प्रदान की जाए।

–स्वास्थ्य विभाग

(7) आगामी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी जाए। किसानों को जंगली जानवरों तथा बंदरों की समस्या से मुक्ति दिलाई जाए। हर जिला मुख्यालय में बंदरों की नसबंदी की व्यवस्था की जाए। किसानों की फसलों के बचाव हेतु फेंसिंग की व्यवस्था की जाए।

–कृषि /वन विभाग

(8) सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में अलग से सिंचाई विंग की व्यवस्था की जाए ताकि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो सके।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(9) परिवहन सुविधाओं के विस्तार हेतु प्रत्येक गांव से तहसील/जिला मुख्यालय के लिये रूट चिन्हित किए जाएं ताकि लोगों को आ रही समस्याओं का समाधान हो सके तथा बेरोजगारों को भी रोजगार उपलब्ध हो सके।

–परिवहन विभाग

(10) नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु प्रयास किए जाएं।

–उद्योग विभाग

(11) सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित किए जाएं। पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए तथा गोबिंदसागर झील में पर्यटकों के लिये नौकायन की व्यवस्था की जाए।

–पर्यटन विभाग

(12) स्वारघाट में विकास खण्ड कार्यालय खोला जाए।

–ग्रामीण विकास विभाग

2. श्री राजेश धर्माणी (घुमारवीं)

(1) विधायकों द्वारा प्रस्तावित प्राथमिकताओं की डीपीआर बनाने से पूर्व निरीक्षण हेतु योजना विभाग में एक टॉस्क फोर्स का गठन किया जाए ताकि योजनाएं स्वीकृत करते समय किसी प्रकार की कठिनाई न आए तथा अनावश्यक विलम्ब को भी टाला जा सके।

–योजना विभाग

(2) बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पॉली हाऊस, दूध संयंत्र केन्द्र, कृषि पर आधारित उद्योग इत्यादि की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए।

–कृषि/पशुपालन विभाग

(3) रेशम उत्पादन तथा इससे सम्बन्धित उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए।

–उद्योग विभाग

(4) मच्छली पालन की ओर लोगों का रूझान बढ़ाया जाए।

–मत्स्य पालन विभाग

(5) शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

–प्रारम्भिक/उच्च शिक्षा विभाग

(6) सीर खड्ड की चैनालाईजेशन गोबिंदसागर झील तक सुनिश्चित की जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(7) दधोल – लदरौर – पट्टा – टौणी देवी राष्ट्रीय उच्च मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।

–लोक निर्माण विभाग

जिला चम्बा

1. श्रीमती रेणू चड्ढा (बनीखेत)

(1) सुरगानी बिजली लाईन पर खर्च की गई एक करोड़ की राशि का भुगतान अभी नहीं हुआ है, जिसे तुरन्त

करवाया जाए। निर्वाचन क्षेत्र में बिजली के मीटर की कमी को भी पूरा किया जाए।

–हि0 प्र0 रा0 वि0 बोर्ड

(2) एचपीसीएल के माध्यम से स्वीकृत प्रोजेक्ट, जिन पर काम नहीं हो रहा है, की ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

–एच.पी.सी.एल.

(3) सलूणी में हैलिपैड की व्यवस्था की जाए।

–पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन

(4) निर्वाचन क्षेत्र में परिवार एवम् कल्याण विभाग की तीन स्कीमों की स्वीकृती शीघ्र प्रदान की जाए।

–परिवार कल्याण एवम् स्वास्थ्य विभाग

(5) पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के बजट में कटौती के कारण सलूणी के विकास की गति धीमी हुई है। इस मद में राशि बढ़ाई जाए।

–योजना विभाग

(6) डल्हौजी सीवरेज स्कीम को पूर्ण करने हेतु धन की व्यवस्था की जाए।

–शहरी विकास विभाग

(7) बनीखेत में टयूबवैल की प्रस्तावित योजना को स्वीकृति प्रदान की जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य

2. श्री कुलदीप सिंह पठानिया (भटियात)

(1) विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत Soil Harvesting Structures बनाने का प्रावधान किया जाए।

–योजना विभाग

(2) द्रमण–सिहुंता सड़क के निर्माण में हुई तकनीकी अनियमिताओं के बारे छानबीन की जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(3) नई स्कीमों के अतिरिक्त चालू स्कीमों की नवीनतम स्थिति की सूचना भी सम्बन्धित विभागों द्वारा विधायकों को समय–समय पर उपलब्ध करवाई जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/ लोक निर्माण विभाग

(4) मनरेगा योजना के अन्तर्गत पक्के रास्ते के निर्माण हेतु प्रावधान किया जाए।

–ग्रामीण विकास

(5) 12वीं पंचवर्षीय योजना में संसाधन दोहन तथा पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए। निजी क्षेत्र के सहयोग से बिजली तथा कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। इसके अतिरिक्त दक्षता विकास की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

– योजना विभाग

जिला कांगड़ा

1. श्री राकेश पठानिया (नूरपुर)

(1) सुडैहली अस्पताल भवन के निर्माण हेतु धन की व्यवस्था की जाए।

–परिवार कल्याण एवम् स्वास्थ्य विभाग

(2) फारेस्ट क्लीयरेंस हेतु एफ.सी.ए. टीम के साथ बैठकों की संख्या को बढ़ाया जाए।

–वन विभाग

(3) नूरपुर में बस स्टैंड का प्रावधान किया जाए।

–परिवहन विभाग

(4) नूरपुर किले में चल रही सरकारी पाठशाला का भवन जर्जर हालत में है। इस पाठशाला के लिए नये भवन का प्रावधान किया जाए तथा जब तक नया भवन नहीं बनता तब तक मिनि सचिवालय में इस पाठशाला को चलाने की अनुमति दी जाए।

–प्राथमिक/उच्च शिक्षा /राजस्व विभाग

(5) नूरपुर अस्पताल में ट्रामा सेंटर तथा आई.सी.यू. का प्रावधान किया जाए।

–परिवार कल्याण एवम् स्वास्थ्य विभाग

(6) फिना सिंह नहर का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ किया जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(7) सुखार एवं सुनैहली वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में साईंस कक्षाएं आरंभ की जाए।

–शिक्षा विभाग

2. श्री देशराज (गंगथ)

(1) निम्न सड़कों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएः

- शहीद पदम सिंह संपर्क मार्ग, भरी
- गंगथ – प्लाक सड़क
- भुड़ंग–समूह सड़क
- गंगस–रागिनी–कटल–मनवार डागा सड़क
- बदरोआ रोड से ब्रीद सड़क

– लोक निर्माण विभाग

(2) गंगथ स्थित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के भवन का निर्माण किया जाए।

–उच्च शिक्षा विभाग

(3) आई.टी.आई. गंगथ में भवन निर्माण के लिये धन का प्रावधान किया जाए।

–तकनीकी शिक्षा विभाग

(4) कंडापतन पुल की मुरम्मत की जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(5) वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डाकरौड़ा में साईंस ब्लॉक का निर्माण किया जाए।

–उच्च शिक्षा विभाग

(6) डाकरौड़ा में पी.एच.सी. का प्रावधान किया जाए।

–परिवार कल्याण एवम् स्वास्थ्य विभाग

(7) गंगथ में 33 के.वी. स्टेशन स्थापित किया जाए।

–हि0प्र0 वि0नि0

(8) गंगथ में पुलिस चौकी स्थापित की जाए।

–पुलिस विभाग

(9) इंदौरा में एस.डी.एम. कार्यालय खोला जाए।

–राजस्व विभाग

3. श्री सुजान सिंह पठानिया (ज्वाली)

(1) स्वां नदी की तरह पौंग डैम के चैनालाईजेशन करने पर विचार किया जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(2) बेरोजगारी दूर करने हेतु कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए तथा पॉली हाऊस के उत्पाद में बिमारी की समस्या का समाधान किया जाए।

–कृषि विभाग

(3) क्षेत्र की अधिकतर सड़के एफ.सी.ए. की अनुमति की वजह से लम्बित हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में एफ.सी.ए. के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्यों के लिए नियमों में ढील देने हेतु मामला केंद्र सरकार से उठाया जाए।

–वन विभाग

(4) नूरपुर अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए ताकि इस क्षेत्र के लोग पठानकोट जाने की बजाए नूरपुर में अपना इलाज करवा सकें।

–परिवार कल्याण एवम् स्वास्थ्य विभाग

(5) निर्वाचन क्षेत्र में अनाधिकृत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

–उद्योग विभाग

(6) गत वर्ष संजोआ तथा जाखड़ खड्डों पर भूमि कटाव को रोकने हेतु दो प्रस्ताव अनुशंशित किये गए थे, जिन पर कार्रवाई की जाए।

–भू–संरक्षण/सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(7) कृषि विभाग द्वारा निर्मित ट्यूवबैलों को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरित किया जाए ताकि इनका रख–रखाव ठीक ढंग से हो सके।

–कृषि/सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

4. श्री निखिल राजौर (जसवां)

(1) डी.पी.आर. बनाने के कार्य में तेजी लाई जाए। जहां आवश्यक हो, उन्हें आऊटसोर्स किया जाए।

–लोक निर्माण / सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(2) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठशालाओं में कमरों का निर्माण विधायकों की संस्तुति पर किया जाए।

–उच्च शिक्षा विभाग

(3) मनरेगा के तहत मजदूरी की अदायगी समय पर सुनिश्चित की जाए।

–ग्रामीण विकास विभाग

(4) किसानों को पॉली हाऊस से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए तथा उनके उत्पाद के विपणन की भी उचित व्यवस्था की जाए।

–कृषि/उद्यान विभाग

(5) पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्राम स्तर तक पर्यटन को बढ़ाया जाए ताकि बेरोजगार युवा इस व्यवसाय को अपना सकें।

–पर्यटन विभाग

(6) छात्रों की कम संख्या के दृष्टिगत प्राथमिक पाठशालाओं को बन्द करने से पहले स्थानीय भौगौलिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाए।

–शिक्षा विभाग

(7) टैरेस औद्योगिक क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

–उद्योग विभाग/ प्रदूषण विभाग/ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

(8) युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने हेतु आधारभूत सुविधाएं उपलबध करवाई जाएं।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(9) अस्पतालों में नवीनतम एवम् आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। निजी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा मनमाने ढंग से फीस लिए जाने की प्रथा पर अंकुश लगाया जाए। पीएचसी टैरेस व कस्वा कोटला में डाक्टरों के खाली पदों को भरा जाए। सीएचसी डाडा के जीर्ण भवन की तुरन्त मुरम्मत करवाई जाए।

–परिवार कल्याण एवम् स्वास्थ्य विभाग

5. श्री योगराज (परागपुर)

(1) देहरा से मगरू तक बस चलाई जाए।

–परिवहन विभाग

(2) पीरसलुई प्राथमिक पाठशाला के क्षतिग्रस्त भवन के पुर्ननिर्माण हेतु तुरन्त कार्रवाई की जाए।

–प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

(3) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठशालाओं में कमरे स्वीकृत करने से पूर्व विधायकों से प्रस्तावनाएं ली जाए।

–प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

(4) स्टोन क्रशर के कारण भूमि कटाव की समस्याओं के समाधान हेतु तुरन्त कार्रवाई की जाए।

–उद्योग विभाग

6. कैप्टन आत्मा राम (राजगीर)

(1) जालग – डली – नालना – डक्यारा सड़क जिसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 2009–10 में बनाई गई थी, को एकमुश्त स्वीकृत किया जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(2) निर्वाचन क्षेत्र में दो रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ROBs के निर्माण हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाए।

–लोक निर्माण विभाग/ योजना विभाग

(3) दमकयारा पाठशाला में निर्माणाधीन भवन के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए।

–प्रारम्भिक/उच्च शिक्षा विभाग

7. श्री प्रवीण कुमार (पालमपुर)

(1) निर्वाचन क्षेत्र में जिन पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं हैं, वहां पर संस्थाएं खोलने के बारे में विचार किया जाए।

–परिवार कल्याण एवम् स्वास्थ्य विभाग

(2) सामुदायिक अस्पताल भवन पालमपुर, जिसकी क्षमता 100 बिस्तरों की है, का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है। उस भवन में तीसरी व चौथी मंजिल में प्राईवेट वार्ड बनाने के बारे में विचार किया जाए।

–परिवार कल्याण एवम् स्वास्थ्य विभाग

(3) घाह, डाढ, बंदला तथा खलेट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में साईंस कक्षाएं शुरू की जाएं। पालमपुर, भवारना तथा पाड़ा में साईंस ब्लॉक तथा जिया, राख, चंदपुर, जो कि देहाती क्षेत्र में हैं, के स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जाए।

–प्रारम्भिक/उच्च शिक्षा विभाग

(4) द्रंग क्षेत्र में विद्युत सब स्टेशन बनाया जाए।

–विद्युत विभाग

(5) पालमपुर क्षेत्र में धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।

–पर्यटन विभाग

(6) पालमपुर में प्रस्तावित रज्जू मार्ग के निर्माण हेतु कार्रवाई की जाए।

–पर्यटन विभाग

(7) पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में न्यूगल खड्ड में अनाधिकृत खनन के कार्य पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए तथा स्थानीय लोगों को उनकी भूमि के साथ रेत–बजरी उठाने की अनुमति प्रदान की जाए।

–उद्योग विभाग

(8) आवारा पशुओं की समस्या के समाधान हेतु तुरन्त कार्रवाई की जाए।

–पशुपालन विभाग

8. श्री विपिन सिंह परमार (सुलह)

(1) कृपाल चंद कूहल भवारना का जीर्णोद्धार किया जाए तथा पेयजल योजना चौकी खलेट से पाईप डालकर इस क्षेत्र की 22 पंचायतों को इस योजना से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(2) स्नातक महाविद्यालय, नोहरा के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए।

–शिक्षा विभाग/लोक निर्माण विभाग

(3) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित भवारना–सुलह–बठारन सड़क की कुछ जगहों पर रेलवे क्रॉसिंग के निर्माण किये जाने पर वांछित कार्रवाई की जाए।

–लोक निर्माण विभाग/ योजना विभाग

(4) भवारना में अटल स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत एंबुलैंस का प्रावधान किया जाए।

–परिवार कल्याण एवम् स्वास्थ्य विभाग

(5) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत कुछ छूट गए पात्र लोगों के पंजीकरण पर उचित कार्रवाई की जाए।

–परिवार कल्याण एवम् स्वास्थ्य विभाग

(6) भदरोल, घराना, चांदर, कुरल इत्यादि क्षेत्रों में पी.एच.सी. निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग के नाम भूमि स्थानांतरित की गई है। अतः इन स्थानों पर स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्मित किए जाएं।

–परिवार कल्याण एवम् स्वास्थ्य विभाग

(7) नव निर्मित सड़कों पर बसें चलाई जाए तथा बेरोजगार युवाओं को परमिट दिए जाएं।

–परिवहन विभाग

(8) बल्लापुर खरोट में उपलब्ध सरकारी भूमि, जहां पर तकनीकी विभाग का भवन निर्मित किया जा रहा है, पर स्वास्थ्य संस्थान खोला जाए।

–राजस्व, तकनीकी शिक्षा तथा
परिवार कल्याण एवम् स्वास्थ्य विभाग

९. श्री संजय चौधरी (कांगड़ा)

(1) कांगड़ा मिनि सचिवालय के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया जाए।

–राजस्व विभाग

(2) वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, सलोल तथा रानीताल के भवन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इन दोनों पाठशालाओं में भवन निर्माण हेतु धनराशि का प्रावधान शीघ्र किया जाए।

–शिक्षा विभाग

(3) मनु और मांजी खड्डों पर भूमि कटाव की समस्या के समाधान हेतु तटीकरण कार्य की प्रगति की जानकारी दी जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(4) कांगड़ा निर्वाचन क्षेत्र की खड्डों पर अवैध खनन पर रोक लगाई जाए तथा सिंचाई हेतु अतिरिक्त कूहलों का निर्माण किया जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(5) धर्मशाला से समीरपुर वाया देहरियां तथा दौलतपुर से जलाड़ी के लिए बंद पड़ी बस सेवाओं को पुनः बहाल किया जाए।

–परिवहन विभाग

(6) नया कांगड़ा की सीवरेज स्कीम में कमियों को शीघ्र पूरा किया जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(7) जिन सड़कों पर एफ.सी.ए. की क्लीयरेंस के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है, पर तुरन्त कार्रवाई की जाए।

–लोक निर्माण/वन विभाग

जिला कुल्लू

1. श्री गोबिंद सिंह ठाकुर (कुल्लू)

(1) मनाली नगर के सौंदर्यकरण योजना के तीव्र कार्यन्वयन हेतु लोक निर्माण, विद्युत तथा सिंचाई विभाग संयुक्त कार्यवाही करे।

–लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा विद्युत विभाग

(2) मनाली शहर के "विज़न डाक्यूमेंट" के कार्यन्वयन पर तुरन्त कार्रवाई की जाए।

–समस्त विभाग

(3) पर्यावरण परिषद का सरलीकरण किया जाए ताकि आबंटित बजट को ठीक ढंग से खर्च किया जा सके। कुल्लू शहर के लिए टूरिज़्म मैगा प्रोजेक्ट की औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण की जाएं।

–पर्यटन विभाग

(4) मनाली के होटल मनालसु, हिडिम्बा कॉटेज के पास एचपीटीडीसी की अप्रयुक्त 12 बीघा भूमि पर होटल प्रबंधन संस्थान खोलने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

–तकनीकी विभाग/ पर्यटन विभाग

(5) राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान को और सुदृढ़ किया जाए ताकि साहसिक पर्यटन को और बढ़ावा मिले।

–पर्यटन विभाग

(6) मनाली में बस अड्डे के निर्माण कार्य को शीघ्र आरम्भ किया जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(7) मनाली बाई पास सड़क के निर्माण हेतु एफ.सी.ए. क्लीयरेंस शीघ्र प्राप्त की जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(8) मनाली स्थित अग्निशमन केंद्र का सुदृढ़ीकरण किया जाए।

–अग्नि शमन विभाग

(9) मनाली पुलिस स्टेश का जीर्णोद्धार किया जाए।

–पुलिस विभाग

(10) हिडिम्बा मंदिर तथा मनाली के आस पास लगते जंगलों को विकसित करने हेतु मास्टर प्लान बनाया जाए।

–पर्यटन विभाग

(11) पतली कूहल में पुलिस थाना तथा अग्निशमन केंद्र की व्यवस्था की जाए।

–अग्नि शमन एवं पुलिस विभाग

(12) मनाली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाए।

–परिवार कल्याण एवम् स्वास्थ्य विभाग

(13) कुल्लू हस्पताल में एनेस्थिसिस्ट विशेषज्ञ की कमी को शीघ्र पूरा किया जाए।

–परिवार कल्याण एवम् स्वास्थ्य विभाग

(14) रामशिला से कुल्लू – मनाली लैफ्ट बैंक सड़क के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए तथा भुगुजोत सड़क के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए। भुगुजोत सड़क के अन्तर्गत टनल निर्माण के लिए जिस निजी अभिकरण को डी.पी.आर. बनाने के कार्य को आउटसोर्स किया गया था, को उसे इसे शीघ्र पूरा करने के लिए कहा जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(15) नाबार्ड द्वारा नग्गर से रूमशु तथा पंजगां से सांचर सड़कों पर जो आपत्तियां लगाई गई हैं, पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। निर्वाचन क्षेत्र की अन्य प्राथमिकता वाली स्कीमों पर भी शीघ्र कार्रवाई की जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(16) जगतसुख और नग्गर के बीच आई.टी.आई. खोली जाए।

–तकनीकी शिक्षा विभाग

(17) पतलीकूहल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए। नग्गर स्वास्थ्य केंद्र एक किनारे पर स्थित है। उसे सड़क के साथ बनाया जाए।

–परिवार कल्याण एवम् स्वास्थ्य विभाग

(18) कटराईं आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ किया जाए।

–आयुर्वेदा विभाग

(19) ओल्ड मनाली में सीवरेज प्रणाली लगाने की संभावनाएं ढूंढी जाएं।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

2. पं0 खीमी राम शर्मा (बंजार)

सपांगड़ी से कंडा सड़क के शेष कार्य को शीघ्र किया जाए। गलोआ धार से रंबी सड़क का निर्माण किया जाए तथा तीर्थन खड्ड पर पुल का निर्माण किया जाए।

–लोक निर्माण विभाग

3. श्री किशोरी लाल (आनी)

(1) प्रस्तावित अवेराघाटू सड़क पर पुल के निर्माण हेतु धन की व्यवस्था की जाए तथा इसका निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(2) निथर में उप तहसील तथा आनी में तहसील कार्यालय खोला जाए।

–राजस्व विभाग

(3) रामपुर के साथ एक विद्युत प्रोजेक्ट के कारण पानी के स्रोत सूख गये हैं। इसकी आपूर्ति के लिए एक परियोजना प्रस्तावित है, जिसकी स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(4) निर्वाचन क्षेत्र में छूटे हुए 800 घरों में बिजली आपूर्ति कार्य हेतु धनराशि शीघ्र उपलब्ध करवाई जाए।

–विद्युत विभाग

(5) निर्वाचन क्षेत्र में 4 एंटी हेल गन स्थापित की जाएं।

–उद्यान विभाग

(6) दलाश तथा निरमण्ड में आई टी आई भवनों के निर्माण कार्य को शीघ्र आरम्भ किया जाए।

–तकनीकी शिक्षा विभाग

(7) ब्रॉ तथा तुहन पंचायतों के पूरे क्षेत्र को टाऊन प्लॉनिंग से बाहर किया जाए।

–नगर एवं ग्राम योजना विभाग

(8) निरमण्ड में बस स्टैंड की व्यवस्था की जाए।

–परिवहन विभाग

(9) निर्वाचन क्षेत्र के शमशर गांव को 'हर गांव की कहानी' योजना में शामिल किया जाए तथा उक्त गांव को विकसित करने हेतु प्रयास किए जाएं।

–पर्यटन विभाग

(10) श्रीखंड महादेव यात्रा के रास्तों के सुधार हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

–ग्रामीण विकास विभाग

(11) उच्च पाठशाला शौली को स्तरोन्नत कर उसे +2 का दर्जा दिया जाए।

–उच्च शिक्षा विभाग

(12) निर्वाचन क्षेत्र की जिला मुख्यालय से दूरी को देखते हुए जिले के अधिकारियों का दो दिन आनी तथा दो दिन निरमण्ड में प्रवास की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो सके।

–उपायुक्त कुल्लू

जिला ऊना

1. श्री बलवीर सिंह (गगरेट)

(1) निर्वाचन क्षेत्र में सड़क निर्माण की योजनाओं पर 38 लाख प्रति कि0मी0 से अधिक की डीपीआर बनाने पर नाबार्ड द्वारा आपत्ति पर स्थिति स्पष्ट की जाए।

–योजना विभाग/नाबार्ड

(2) दौलतपुर कॉलेज में साईंस कक्षाएं सरकारी स्तर पर शुरू की जाएं।

–उच्च शिक्षा विभाग

(3) गगरेट बाजार में बनाई गई आवासीय कालोनी को विकास खण्ड कार्यालय के साथ चयनित भूमि पर स्थानांतरित किया जाए तथा उस स्थान पर व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया जाए।

–ग्रामीण विकास विभाग

(4) गगरेट में नगर पंचायत की 37 कनाल भूमि पर पार्क निर्मित किए जाने का प्रावधान किया जाए ताकि हो रहे अवैध कब्जों को रोका जा सके।

–शहरी विकास विभाग

(5) पुरानी पुलिस चौकी गगरेट के साथ 1.4 कनाल भूमि को नगर पंचायत को स्थानांतरित किया जाए।

–पुलिस विभाग

(6) गगरेट में उप तहसील खोली जाए।

–राजस्व विभाग

(7) राष्ट्रीय उच्च मार्ग गगरेट तथा अंबोटा शिवबाड़ी सड़क पर जाम की समस्या के समाधान के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(8) गगरेट स्थित एक मिल की बेकार पड़ी 44 कनाल भूमि को लीज़ पर दे दिया जाए अन्यथा वहां वृक्षारोपण करके आय के साधन सृजित किए जाएं।

–राजस्व एवं वन विभाग

(9) वर्षा जल संग्रहण स्ट्रक्चर की लम्बित प्रस्तावनों को स्वीकृत किया जाए।

–कृषि विभाग

(10) विकेन्द्रीकृत नियोजन नीति के अन्तर्गत जिलों को और अधिक धनराशि जारी की जाए।

–योजना विभाग

2. श्री राकेश कालिया (चिंतपूर्णी)

(1) चिंतपूर्णी – संडोली बाई पास सड़क के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(2) किनू से शीतला मंदिर तक बाई पास सड़क के निर्माण हेतु तुरन्त कार्यवाही की जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(3) हैंडपंप न लगाकर इनके स्थान पर पेयजल योजनाओं का निर्माण किया जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(4) चिंतपूर्णी स्थित बहुद्देशीय परिसर के निर्माण को गति प्रदान की जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(5) चिंतपूर्णी स्थित पार्किंग को बहुमंजिला कार पार्किंग में परिवर्तित किया जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(6) किनू में आवारा पशुओं के लिए गौ–सदन का निर्माण करवाया जाए।

–पशु पालन विभाग

(7) अंब उच्च मार्ग के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(8) स्वां नदी की सहायक नदियों के तटीकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(9) निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलवाई जाए।

–वन विभाग

३. श्री मुकेश अग्निहोत्री (संतोखगढ़)

(1) बीट क्षेत्र सिंचाई योजना के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(2) निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत 34 ट्यूबवैल लगाने का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(3) स्वां चैनालाईजेशन के चौथे चरण का कार्य शीघ्र शुरू किया जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(4) बाथड़ी–बाथू में भूमि कटाव की समस्या के समाधान हेतु वांछित कार्रवाई की जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(5) क्षेत्र में ई.एस.आई अस्पताल खोला जाए।

–परिवार कल्याण एवम् स्वास्थ्य विभाग

(6) किसानों के ट्रैक्टर खरीदने के लंबित प्रकरणों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए।

–कृषि विभाग

(7) आवारा पशुओं/जंगली जानवरों से किसानों की फसलों की रक्षा की जाए।

–वन / पशु पालन विभाग

(8) बाथड़ू में पुलिस चौकी खोली जाए।

–पुलिस विभाग

(9) निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे क्रशरों पर अंकुश लगाया जाए।

–उद्योग विभाग

(10) एच. आर. कास्टिंग फैक्टरी द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क तथा बाथू गांव को हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु वांछित कार्रवाई शीघ्र की जाए।

–उद्योग विभाग

(11) पेपर मिल को उपलब्ध करवाई गई भूमि की छानबीन की जाए।

–उद्योग विभाग

(12) ब्लड बैंक में टैक्निशयन की नियुक्ति की जाए।

–परिवार कल्याण एवम् स्वास्थ्य विभाग

(13) समस्त स्कीमों के समयबद्ध समापन पर ठोस कार्रवाई की जाए।

–लोक निर्माण / सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(14) सभी संस्तुत स्कीमों की डी.पी.आर. जनवरी, 2012 से पूर्व तैयार की जाएं।

–लोक निर्माण/सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

जिला हमीरपुर

1. श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू (नादौन)

(1) बडाह में कृषि विश्वविद्यालय की उपलब्ध 500 कनाल भूमि को स्पाईस बोर्ड को लीज़ पर दिए जाने की व्यवस्था की जाए ताकि स्पाईस बोर्ड वहां पर अपनी परियोजना शुरू कर सके।

–उद्योग विभाग/ कृषि विवि पालमपुर

(2) नादौन केंद्रीय स्कूल जहां 10वीं तक कक्षाएं चलाने की प्रस्तावना है के लिए भूमि की व्यवस्था की जाए।

–राजस्व विभाग

(3) ए.पी.आई.डी.ए. द्वारा स्वीकृत ग्रेडिंग प्रोजेक्ट के लिये जिस भूमि का चयन किया गया था, की स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जाए।

–कृषि एवं उद्यान विभाग

(4) टैंडर अवार्ड करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए तथा इसे समयबद्ध बनाया जाए।

–लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(5) सुरंग बनाते समय यातायात घनत्व का विशेष ध्यान रखा जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(6) धनेटा से बंगाणा सुरंग का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(7) ऐसे स्वीकृत कार्य, जिनके निर्माण में निजी भूमि के अधिग्रहण की समस्या आ रही है, के लिए नियमानुसार भू अधिग्रहण प्रक्रिया के माध्यम से भू–अधिग्रहण हेतु वांछित कार्रवाई की जाए।

–राजस्व/ लोक निर्माण विभाग

(8) नादौन स्थिति मिनि सचिवालय के निर्माण को अति शीघ्र पूर्ण किया जाए।

–सामान्य प्रशासन एवं लोक निर्माण विभाग

(9) निजी शिक्षण संस्थानों के लिये निर्धारित **"कोई लाभ –कोई नुकसान नहीं"** के नियम में संशोधन किया जाए ताकि प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थानों का प्रसार हो तथा शिक्षा में गुणवत्ता आए।

–शिक्षा विभाग

2. श्रीमती उर्मिल ठाकुर (हमीरपुर)

(1) निम्न योजनाओं का विस्तार व सुधार किया जाएः–

- उठाऊ पेयजल योजना, झनयारा बस्सी
- सिंचाई योजना, मसयाना
- सिंचाई योजना, लौंगणी मथान
- उठाऊ पेयजल योजना टिक्कर डेरा चरोट

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(2) पुंग और ब्यास नदी पर लगाए गए क्रशरों की वजह से सिंचाई एवं पेयजल योजना पर कुप्रभाव पड़ा है। इस समस्या के समाधान हेतु तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जाए।

–उद्योग विभाग

(3) सुजानपुर को एपीडीआरपी स्कीम के अन्तर्गत लाए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

–ग्रामीण विकास विभाग

(4) उहल, कक्कड़ तथा चौरी में कनिष्ठ अभियन्ता के खाली पदों को शीघ्र भरा जाए। मसयाना तथा अमरोह सैक्शन में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पूर्ववत् रखे जाएं।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(5) नवनिर्मित सिंचाई/पेयजल योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने हेतु स्टॉफ की कमी को पूरा किया जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(6) पंचायतों को हस्तांतरित स्कीमों का कार्यान्वयन ठीक ढंग से सुनिश्चित किया जाए। पंचायतों में रखे गए कामगारों की मजदूरी बढ़ाने के बारे में भी विचार किया जाए।

–ग्रामीण विकास विभाग

(7) पंचायतों को हस्तांतरित बहुत से हैंड पम्प, जो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, को सिंचाई एवम् जन स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित किया जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(8) कन्या उच्च पाठशाला, सुजानपुर को स्तरोन्नत किया जाए।

–शिक्षा विभाग

(9) नई सड़कों पर बस रूट दिए जाने के बारे में विचार किया जाए।

–परिवहन विभाग

(10) सुजानपुर में एक ऐतिहासिक नौण है। इसमें पूरे बाजार का गंदा पानी गिरता है। इस नौण को चैनालाईजेशन किया जाए तथा वहां पर सब्जी मार्कीट खोली जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/कृषि विभाग

(11) जोनल हस्पताल हमीरपुर में ओवर हैड टैंक बनाया जाए।

–परिवार कल्याण एवम् स्वास्थ्य विभाग

(12) जोनल हस्पताल हमीरपुर के समीप विद्युत ट्रांसफार्मर लगाया जाए।

–परिवार कल्याण एवम् स्वास्थ्य विभाग

(13) सैनिक स्कूल की मुरम्मत के लिये धनराशि की व्यवस्था की जाए।

सैनिक कल्याण विभाग

(14) सुजानपुर में ऑडोटोरियम का निर्माण किया जाए।

–शहरी विकास विभाग

(15) हमीरपुर में पेयजल समस्या का निदान किया जाए तथा पार्किंग की व्यवस्था की जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/शहरी विकास विभाग

(16) हमीरपुर में स्टेडियम का निर्माण किया जाए।

–शहरी विकास विभाग

3. श्री बलदेव शर्मा (नादौनता)

(1) विधायक प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़कों/ पुलों को स्वीकृत करने हेतु प्रयास किए जाएं तथा उनका निर्माण शीघ्र सुनिश्चित किया जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भोटा का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

–परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग

(3) हमीरपुर जिला के भोटा में तहसील कार्यालय खोला जाए।

–राजस्व विभाग

(4) गलोड़ में थाना खोला जाए।

–पुलिस विभाग

(5) नादौनता क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य विभागों के रिक्त पड़े पदों को भरा जाए।

–समस्त विभाग

जिला लाहौल एवं स्पिति

1. डॉ0 राम लाल मारकण्डे (लाहौल स्पिति)

(1) लाहौल स्पिति क्षेत्र के लिये आबंटित बजट में कटौती न की जाए और यदि कोई स्कीम अव्यवहार्य है तो बदलने की अनुमति प्रदान की जाए।

–योजना / जनजातीय विभाग

(2) सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को स्थल निरीक्षण तथा स्थानीय विधायक से परामर्श उपरान्त ही अव्यवहार्य घोषित किया जाए तथा उनके स्थान पर नई स्कीमों का चयन किया जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(3) आई.टी.आई., शमशी से लाहौल स्थानान्तरित ट्रेड से सम्बन्धित इंस्ट्रक्टर शीघ्र लाहौल आई.टी.आई में नियुक्त किए जाएं।

–तकनीकी शिक्षा विभाग

(4) बाढ़ से क्षतिग्रस्त लिगटी प्रोजेक्ट, जिनके लिए 50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हो चुकी है। इसके निर्माण हेतु तुरन्त कार्रवाई की जाए।

–हिम ऊर्जा

(5) रोंग–टोंग प्रोजेक्ट की दयनीय हालत के सुधार हेतु तुरन्त आवश्यक कार्रवाई की जाए।

–विद्युत विभाग

(6) पूह से लोसर तक बिछाई जाने वाली 66 के.बी.ए.विद्युत लाईन जिसके लिए 32 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, को शीघ्र पूरा किया जाए।

–विद्युत विभाग

(7) कुकम सेरी कॉलेज में प्रधानाचार्य तथा दो प्रवक्ताओं के खाली पदों को शीघ्र भरा जाए। अन्य विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाए। ऐसे खाली पड़े पदों को अनुबन्ध के आधार पर भरने हेतु भी विचार किया जाए।

–समस्त विभाग

जिला किन्नौर

1. श्री तेजवंत नेगी (किन्नौर)

(1) पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से मानसरोवर यात्रा को जिला किन्नौर से शुरू करने हेतु प्रयास किए जाएं।

–पर्यटन/सामान्य प्रशासन विभाग

(2) विद्युत परियोजनाओं से प्रभावितों लोगों को परियोजना लागत का एक प्रतिशत राशि दिए जाने के बारे में विचार किया जाए।

–विद्युत विभाग

(3) जनजातीय क्षेत्रों में हैलिटैक्सी की सुविधा शुरू करने हेतु प्रयास किए जाएं।

–पर्यटन/सामान्य प्रशासन विभाग

(4) बुद्ध से वाया कटगांव, स्पिति को जोड़ने वाले रास्ता जिसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(5) छितकुल से उत्तराखंड को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण की सम्भावनाओं पर विचार किया जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(6) **'हर घर कुछ कहता है' तथा 'हर गांव की कहानी'** जैसी योजनाएं पर्यटकों का आकर्षित करने में सहायक सिद्ध हुई हैं तथा किन्नौर जिला में 47 युनिट इन योजनाओं के तहत पंजीकृत हुए हैं। ऐसी योजनाओं को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाएं।

–पर्यटन विभाग

(7) हंगण घाटी–चांगो मलिंग–नाकों–लाहौल स्पिति की 66 के वी की विद्युत लाईन के निर्माण हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाए।

–विद्युत विभाग

(8) नदियों के किनारे, जहां भूमि कटाव हो रहा है, वहां भू संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जाएं।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जारी दिशा निर्देश

(1) माननीय विधायकों की मध्यावधि समीक्षा के दौरान उठाए गए मुद्दों पर समस्त विभाग स्पष्ट उत्तर दें तथा नवीनतम स्थिति से योजना विभाग के साथ–2 सम्बन्धित विधायकों को भी अवगत करवाएं। इन बैठकों में उठाए गए मुद्दों का दायित्व सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवों तथा विभागाध्यक्षों का होगा।

–समस्त विभाग

(2) विधायक प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने हेतु सेवानिवृत अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएं तथा यदि आवश्यक हो तो परियोजना रिपोर्ट बनाने के कार्य को आउटसोर्स किया जाए।

–लोक निर्माण विभाग/
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(3) योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने से पूर्व सम्बन्धित विधायकों से विचार विमर्श किया जाए ताकि भूमि विवाद इत्यादि समस्याओं का निपटारा शीघ्र हो सके।

–लोक निर्माण विभाग/
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(4) पेयजल एवं सिंचाई की ज्यादा से ज्यादा स्कीम ए.आर. पी./ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत प्रस्तावित की जाएं, ताकि भारत सरकार से मिलने वाली केन्द्रीय सहायता का पूरा उपयोग किया जा सके।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(5) अवैध खनन की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा कितने चालान काटे गए तथा कितने ट्रैक्टर पकड़े गए इत्यादि पर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाए।

–उद्योग विभाग

(6) पॉली हाऊसिस के उत्पाद में बीमारी की रोकथाम हेतु कृषि विभाग तथा कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारी/विशेषज्ञ स्थल निरीक्षण करे तथा मौके पर उसका समाधान करने का प्रयास करें।

–कृषि विभाग

(7) कृषि तथा उद्यान के उत्पादों के विपणन में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु राष्टीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समूहों से सम्पर्क किया जाए।

–कृषि/उद्यान विभाग

(8) किसानों को जैविक खेती हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

–कृषि विभाग

(9) नौरा, नगरोटा तथा पद्धर महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए।

–लोक निर्माण विभाग

(10) जिन पेयजल योजनाओं में सिल्ट को रोकने का प्रावधान नहीं है, के लिए वांछित व्यवस्था की जाए।

–सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(11) पाठशाला भवनों का निर्माण योजनाबद्ध ढंग से किया जाए ताकि उपलब्ध भूमि का पूरा उपयोग किया जा सके। बहुमंजिला भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। पाठशाला भवनों के निर्माण में स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

–प्राथमिक/उच्च शिक्षा विभाग

(12) अनुसूचित जाति उप–योजना के अन्तर्गत टोकन बजट की बजाय पूरी राशि का प्रावधान किया जाए ताकि उप–योजना के अन्तर्गत उपलब्ध राशि का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

–अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक मामले विभाग

(13) लाहौल स्पिति जिले की भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत कार्य दिवस कम होने की वजह से निर्माण कार्य समयबद्ध तीरके से पूरे किए जाएं।

–समस्त विभाग

(14) विधायक प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत चालू स्कीमों की सूचना समय–समय पर माननीय विधायकों को दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

–लोक निर्माण/ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

*****